भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1702

जिसका उत्तर 10 दिसम्बर, 2025 को दिया जाना है ।

19 अग्रहायण, 1947 (शक)

पलक्कड़ में इलेक्ट्रॉनिक्स कलपुर्जे के निर्माण संयंत्रों की स्थापना

1702. श्री वी.के. श्रीकंदन :

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार इलेक्ट्रॉनिक्स कलपुर्जे के विनिर्माण योजना के अंतर्गत 17 नई परियोजनाओं को मंजूरी दी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह भी सच है कि सात परियोजनाओं की घोषणा के बाद यह घोषणाओं की दूसरी कड़ी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार कंपनियों को केरल के पलक्कड़ जैसे उन क्षेत्रों में अपने संयंत्र स्थापित करने की सलाह देगी जहां अभी ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से **(ग):** भारत सरकार की नीतियां माननीय प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण से प्रेरित हैं। इसका उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के लिए एक संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है।

हमने देश में तैयार उत्पादों के निर्माण के साथ अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स यात्रा शुरू की और फिर मॉड्यूल विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया। अब उप-मॉड्यूल/घटकों और इसके निर्माण में जाने वाले कच्चे माल, उपकरण और मशीनरी को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

पिछले 11 वर्षों में भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण का काफी विस्तार हुआ है। हाल के वर्षों में भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण इकाइयों द्वारा मूल्यवर्धन में भी काफी वृद्धि हुई है। इसे निम्नलिखित आँकड़ों से देखा जा सकता है:

#	2014-15	2024-25	टिप्पणियां
इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं का उत्पादन (₹)	~1.9 लाख करोड़	~11.3 लाख करोड़	6 गुना बढ़ा
इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं का निर्यात (₹)	~0.38 लाख करोड़	~3.3 लाख करोड़	8 गुना बढ़ा
मोबाइल फोन का उत्पादन (₹)	~0.18 लाख करोड़	~5.5 लाख करोड़	28 गुना बढ़ा
मोबाइल फोन का निर्यात (₹)	~0.01 लाख करोड़	~ 2 लाख करोड़	127 गुना बढ़ा

यह परिवर्तन सरकार की इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण रणनीति द्वारा संभव हुआ था। पिछले 11 वर्षों में कई पहलें की गई हैं। इसमे शामिल है:

- बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई)
- आईटी हार्डवेयर के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई)
- इलेक्ट्रॉनिक घटकों और सेमीकंडक्टर्स के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए योजना (एसपीईसीएस)
- इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी और ईएमसी 2.0) योजना
- सार्वजनिक खरीद में घरेलू स्तर पर निर्मित उत्पादों को प्राथमिकता देने के लिए सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को प्राथमिकता) आदेश 2017
- टैरिफ ढांचे को युक्तिसंगत बनाने, पूंजीगत वस्तुओं पर मूल सीमा शुल्क में छूट आदि सहित कराधान में सुधार किए गए हैं।
- लागू कानूनों/विनियमों के अधीन इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति

इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम (ईसीएमएस)

इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को और मजबूत करने के लिए, सरकार ने ईसीएमएस लॉन्च किया। यह प्रतिरोधक, कैपेसिटर, इंडक्टर्स, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, सब-असेंबली, इलेक्ट्रो-मैकेनिकल आदि जैसे घटकों के निर्माण को बढ़ावा देता है।

इस योजना को उद्योग जगत से अब तक अभूतपूर्व प्रतिक्रिया मिली है। 59,350 करोड़ रुपये के लक्षित निवेश के मुकाबले 1.15 लाख करोड़ रुपये के निवेश मूल्य वाली परियोजनाओं के लिए आवेदन प्राप्त हुए हैं।

अनुमोदन की दूसरी किश्त पहले स्वीकृत सात आवेदनों की निरंतरता में है। सरकार ने इस योजना के तहत अब तक 24 आवेदनों को मंजूरी दी है, जिनमें से 17 आवेदनों को दूसरी किश्त में मंजूरी दे दी गई है।

इन 24 आवेदनों में 12,704 करोड़ रुपये के निवेश, 109,517 करोड़ रुपये के उत्पादन और 17,003 प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने का अनुमान लगाया गया है।

सरकार ने ईसीएमएस योजना में भाग लेने के लिए उद्योग से आवेदन आमंत्रित किए थे जो अखिल भारतीय प्रकृति की है। राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित सहायक नीति और व्यापार करने में आसानी के अन्य उपायों को ध्यान में रखते हुए विनिर्माण इकाइयों का स्थान उद्योग द्वारा तय किया जाता है।

*****